

दिनांक: 20.08.2024

समय : 09:00 ए.एम.

प्रादेशिक समाचार  
आकाशवाणी जयपुर-अजमेर

- केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती 25 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी-सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए समिति का होगा गठन।
- विभिन्न संगठनों की ओर से कल भारत बंद के आह्वान को देखते हुए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कदाचार रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस पैरालिंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की, कहा-भारत का गौरव, खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है।

सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा तैनाती में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इसके तहत मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों की व्यक्तिगत मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता की घटना के बाद केंद्रीय कानून की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किए हैं। अस्पतालों में रेजिडेंट के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे ड्यूटी रूम और काम के घंटे जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी-एसटी आरक्षण के सम्बंध में पिछले दिनों दिए गये निर्णय को देखते हुए कुछ संगठनों द्वारा कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखें, अफवाह फैलाने और भडकाने वाली पोस्ट डालने तथा शेयर करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें तथा गलत तथ्य का सोशल मीडिया और प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में खंडन जारी रखें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बंद के आयोजकों के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा जुलूस संबंधी जानकारी अन्य अधिकारियों से साझा करें। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेंज आईजी, सम्भागीय आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टरों से फीडबैक लिया। फीडबैक में शामिल अधिकारियों ने बताया कि इंटेलेजेंस के माध्यम से लगातार सूचना जुटाकर सम्बंधित अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। बैठक में पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू और एसीएस आनन्द कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 341 और 342 के तहत केंद्रीकृत सूची का समूह बनाया गया है। इस समूह में जातियों के उप वर्गीकरण का प्रावधान नहीं है, ना ही क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार जो भी अंतिम निर्णय लेगी, राज्य सरकार उसी के अनुसार कदम उठाएगी। श्री गहलोत ने कल जयपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार उप वर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकार को है।

केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। श्री मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान लेटरल एंट्री की

शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह समेत कई अधिकारी लेटरल एंट्री द्वारा सरकार में शामिल हुए थे। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए लेटरल एंट्री को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया है।

.....

भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई ने कदाचार को रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नए नियम, ऋण देने तथा लेने वाली ईकाइयों को ऋण से संबंधित वृद्धि या आश्वासन देने की पेशकश करने से रोकते हैं। दिशा-निर्देशों में यह सुनिश्चित किया गया है कि ऋणदाता लेन-देन में मूलधन और ब्याज या दोनों के संदर्भ में होने वाले पूरे नुकसान को वहन करें। ऋण देने या लेने वाली ईकाइयां, अपनी सेवाओं को निवेश उत्पादों के रूप में प्रचारित नहीं कर सकती हैं और वे ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज दोनों पर होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए जवाबदेह हैं।

.....

उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र देवराज की कल शाम अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। देवराज का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच, छात्र की अंतिम यात्रा निकाली गई। देवराज की मृत्यु की सूचना के बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि आज तक के लिए बढ़ा दी गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। श्री बेढम ने कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें।

इधर, कल छात्र की मौत के बाद अस्पताल के बाहर आक्रोशित लोगों की भीड़ को कम करने के लिए संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल सहित अन्य जनप्रतिनिधि परिवार और समाज के साथ समझाइश में जुटे रहे। समझौता वार्ता के बाद विधायक ताराचंद जैन ने मीडिया से बातचीत में बताया पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपये और एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। एजेंसी के अनुसार हालांकि प्रशासन ने स्थायी नौकरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सहमति दी है। परिवार को सुरक्षा की गारंटी, तुरंत न्याय के लिए मामला केस ऑफिसर स्कीम में देने पर भी सहमति बनी है।

.....

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालिंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पैरालिंपिक गेम्स इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत का गौरव पेरिस में खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब एक खिलाड़ी किसी खेल के इतने बड़े मंच पर पहुंचता है तब वह उसके साहस, समर्पण और त्याग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पैरा एथलीट इस मुकाम पर पहुंचकर यह दर्शाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वह कितने मजबूत हैं।

.....

केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस बार पैरालिंपिक में भारत अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। उन्होंने बताया कि पैरालिंपिक में 84 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

.....

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है। हनुमानगढ में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित कर श्री गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। करौली और जैसलमेर में कांग्रेस कार्यालय पर संगोष्ठी रखी गई है। भीलवाडा में कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं।